जय सिंह सेखों, जे. के समक्ष

हरजीत सिंह,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 2907

30 मई, 1990.

भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 14—पंजाब पुलिस नियम, 1934—समयपूर्व सेवानिवृत्ति–अवर प्रविष्टियों की अद्यतन सूचना नहीं–याचिकाकर्ता को कार्यदक्षता बार पार करने से रोका गया–इसके खिलाफ दावा असफल–अवर प्रविष्टियों की गैर-सूचना महत्वपूर्ण नहीं–समयपूर्व सेवानिवृत्ति का समर्थन किया गया।

यह माना गया कि हाल ही के अतीत के सेवा रिकॉर्ड का विचार किया गया है और सेवा रिकॉर्ड की पुरानी और बासी प्रविष्टियों को उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश के आधार के रूप में नहीं बनाया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता को अवर प्रविष्टियों की गैर-सूचना का कोई महत्व नहीं है क्योंकि स्वीकार्य रूप से याचिकाकर्ता को कार्यदक्षता बार पार करने की अनुमति नहीं थी और उसके खिलाफ दावा भी असफल रहा जिसका अर्थ है कि वह योग्य और कुशल अधिकारी नहीं था और इस प्रकार उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति जनहित में थी और नियमों की भावना का उल्लंघन नहीं करती। (पैरा 8)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका यह प्रार्थना करती है कि:–

(i) अनुच्छेद P-19 दिनांक 7 जुलाई, 1979 और अनुच्छेद P-20 दिनांक 8 अगस्त, 1979 के आदेशों को रद्द करने के लिए एक रिट जारी की जाए।

(ii) रिकॉर्ड्स को मंगाया जाए और परीक्षण किया जाए।

(iii) इस माननीय अदालत द्वारा मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं।

(iv) याचिकाकर्ता को अनुच्छेदों की प्रमाणित प्रतियाँ दाखिल करने से छूट दी जाए।

(v) याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

(vi) सेवानिवृत्ति के आदेशों को रद्द करने के बाद, ऐसे निर्देश जारी किए जाएं कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में माना जाए।

जे. एस. रंधावा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

एस. एस. अहलावत, डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

जे. एस. सेखों, जे.

1) याचिकाकर्ता को वर्ष 1941 में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में भर्ती किया गया था। उन्होंने फरवरी 1942 में सफलतापूर्वक बेसिक तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रेड III पूरा किया। उन्होंने 1944 में सेना सिग्नल के ग्रेड II ट्रेड बोर्ड टेस्ट भी पास किया। वर्ष 1946 में, जब वे ग्रेड I कोर्स का प्रशिक्षण कर रहे थे, उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण सेना से मुक्त किया गया। याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड सेना की सेवा के दौरान उत्कृष्ट रहा और उन्हें "इंडियन सर्विस मेडल" और "वार मेडल" भी प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता को जनवरी 1948 में पंजाब पुलिस वायरलेस मुख्यालय, शिमला में कांस्टेबल/वायरलेस मैकेनिक के पद पर चयनित और नियुक्त किया गया। उनके अच्छे और संतोषजनक काम के कारण उन्हें 1 जून, 1948 से रेडियो तकनीशियन/सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। याचिकाकर्ता को देश के विभाजन के बाद भारत के हिस्से में आने वाले पुराने उपकरणों के निर्माण, स्थापना, मरम्मत और संशोधन के काम सौंपे गए। उनके अच्छे प्रदर्शन की मान्यता में, उन्हें 1 जुलाई, 1948 से पर्यवेक्षक/उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नति दी गई। याचिकाकर्ता को 1 फरवरी, 1952 से उप-निरीक्षक रखरखाव के रूप में पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता की सेना में चार वर्ष की सेवा को पुलिस वायरलेस विभाग में पेंशन आदि के उद्देश्य से योग्य अनुभव के रूप में गिना गया। याचिकाकर्ता को आगे 28 अगस्त, 1963 को श्री प्रेम नाथ के पुलिस उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नति के कारण बनी स्थायी रिक्ति के खिलाफ इंस्पेक्टर रखरखाव/प्रभारी पुलिस रेडियो कार्यशाला और स्टोर के रूप में पदोन्नति दी गई। पंजाब राज्य के पुनर्गठन के अवसर पर, याचिकाकर्ता को 1 नवंबर, 1966 से हरियाणा राज्य के इंस्पेक्टर प्रभारी पुलिस रेडियो कार्यशाला और स्टोर के रूप में आवंटित किया गया। याचिकाकर्ता को तत्कालीन सहायक पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी और प्रशिक्षण, हरियाणा द्वारा 1 नवंबर, 1966 से हरियाणा पुलिस वायरलेस के इंस्पेक्टर के पद के स्वतंत्र प्रभारी के रूप में अच्छी रिपोर्ट दी गई। याचिकाकर्ता को तत्कालीन सहायक पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी और प्रशिक्षण, हरियाणा द्वारा 1 नवंबर, 1966 से 22 सितंबर, 1967 तक हरियाणा पुलिस वायरलेस के इंस्पेक्टर के पद के स्वतंत्र प्रभारी के रूप में अच्छी रिपोर्ट दी गई थी। याचिकाकर्ता को उनकी सेवाओं की मान्यता में 27 मार्च, 1967 को आदेश पुस्तिका संख्या 130 के तहत 50 रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता को 25 जनवरी, 1968 के आदेश द्वारा हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उप-निरीक्षक रखरखाव के पद पर वापस लाया गया था, इस आधार पर कि उन्होंने समन्वयन निदेशालय (पुलिस वायरलेस), भारत

सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित रेडियो तकनीशियन/ऑपरेटर ग्रेड । टेस्ट में योग्यता हासिल नहीं की थी। याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए प्रतिनिधित्व को 22 मई, 1968 के पत्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने फिर उच्च न्यायालय में C.W.P. संख्या 2025 में 1968 में अपने पदावनति को चुनौती दी, जिसे 9 सितंबर, 1969 को स्वीकार किया गया और जिसे 1969 S.L.P. 845 के रूप में रिपोर्ट किया गया। याचिकाकर्ता के पदावनति के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वायरलेस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले कार्यकारी निर्देश याचिकाकर्ता की वास्तविक पदोन्नति के बाद जारी किए गए थे। उक्त रिट याचिका में प्रतिवादियों में से एक श्री अमृत लाल ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ L.P.A. संख्या 524 का 1969 में दायर किया, जिसे 7 नवंबर, 1969 को डिवीजन बेंच द्वारा लिमिने में खारिज कर दिया गया। इस बीच, एक पिशोरी लाल सोधी ने सिविल मिस्क। आवेदन संख्या 5889 का 1969 में उक्त रिट याचिका में उल्लिखित निर्णय को खारिज करने के लिए दायर किया, इस आधार पर कि उन्हें एक प्रतिवादी के रूप में व्यवस्थित नहीं किया गया था हालांकि वे रिट याचिका के लिए एक आवश्यक पक्ष थे। यह आवेदन 6 नवंबर, 1969 को उच्च न्यायालय द्वारा इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया गया कि पिशोरी लाल के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा जो वह अब दावा कर रहे हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 (वर्तमान याचिकाकर्ता) उनसे स्पष्ट रूप से वरिष्ठ थे और उनका पदोन्नति का मौका वर्तमान याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद होता। उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, विभाग ने,—विदेश 26 नवंबर, 1969 को जारी आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के पदावनति के आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि चूंकि उसने हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश को उपर्युक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके खिलाफ पक्षपाती और नाराज महसूस कर रहे थे और परिणामस्वरूप उक्त रिट याचिका की सूचना प्राप्त होने के बाद, 23 सितंबर, 1967 से 21 मार्च, 1968 तक की अवधि के लिए गोपनीय रिपोर्टों में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की गईं। याचिकाकर्ता की रेडियो सिद्धांत के ज्ञान के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियाँ, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने ग्रेड । परीक्षा में तीन बार असफलता प्राप्त की थी, उन्हें 14 अगस्त, 1968 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। यह और बताया गया है कि इन्हीं टिप्पणियों को 1968-1969 में फिर से दोहराया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए प्रतिनिधित्व को संक्षेप में खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये टिप्पणियाँ मुख्य रूप से इस आधार पर थीं कि उन्होंने ग्रेड । परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन चूंकि यह उनके इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति के लिए एक शर्त पूर्व नहीं थी जैसा कि 9 सितंबर, 1969 को C.W.P. संख्या 2025 में उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया था, ये टिप्पणियाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं थीं। यह और बताया गया है कि 1970 में याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ मुद्दे पर आंदोलन

के दौरान किए गए अच्छे काम के लिए तारीफ प्रमाणपत्र (क्लास III) के साथ 35 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था। 1969-1970 के लिए याचिकाकर्ता का काम और आचरण संतोषजनक और अच्छा रहा। फिर 1970-1971 में याचिकाकर्ता को रेडियो सिद्धांत के ज्ञान में कमी और ग्रेड I परीक्षा में याचिकाकर्ता की असफलता के आधार पर बार-बार और अनावश्यक टिप्पणियां बताई गईं। इस अवधि के लिए याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व भी खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि श्री तरलोक नाथ, तत्कालीन पुलिस वायरलेस के अधीक्षक, उनके गोपनीय रिपोर्टों में लगातार अनावश्यक और अनुपयुक्त टिप्पणियां कर रहे थे, हालांकि उपरोक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा ग्रेड I परीक्षा पास करना इंस्पेक्टर के पद के लिए याचिकाकर्ता की सेवा की शर्त नहीं बताई गई थी। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात करने की मांग की और इस संबंध में 15 मई, 1972 को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। इस प्रतिनिधित्व के साथ, याचिकाकर्ता ने 9 अक्टूबर, 1968 को लिखे गए पुलिस अधीक्षक के पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की जिसमें दिखाया गया था कि बाद वाले के पास उनकी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताओं के समर्थन में कोई डिग्री नहीं थी। यह प्रतिनिधित्व उचित चैनल के माध्यम से भेजा गया था और जब यह मामला पुलिस अधीक्षक (वायरलेस) श्री तरलोक नाथ के संज्ञान में आया, तो उन्होंने 3 जुलाई, 1972 को याचिकाकर्ता को एक शो-कॉज नोटिस जारी कर दिया, उन्हें बताने के लिए कि वह क्यों नहीं फटकारे जाएं क्योंकि उन्होंने उपरोक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड से उत्पन्न किया था। अंततः, पुलिस अधीक्षक (वायरलेस) ने 27 जुलाई, 1972 को याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ हरियाणा के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री पी. सी. वाधवा के समक्ष अपील की, जिन्होंने 9 मार्च, 1973 को अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि इस बीच 25वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर याचिकाकर्ता को 1947 से 1972 तक दी गई अच्छी सेवा के लिए वर्षगांठ पदक प्रदान किया गया था। फिर से, 1971-1972 के लिए, वही प्रतिकूल टिप्पणियाँ याचिकाकर्ता को बताई गईं और उनके द्वारा दायर किए गए प्रतिनिधित्व को भी 2 अगस्त, 1973 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि, दूसरी ओर, इसी प्रतिनिधित्व के संबंध में, हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक ने उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस एच.ए.पी. को इस मामले को देखने और तरलोक नाथ, पुलिस अधीक्षक (वायरलेस) द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को दोहराने के बारे में अपनी स्वतंत्र राय देने के लिए कहा, - विद्युत संख्या 17469/B (i) दिनांक 27 दिसंबर के अनुसार। फिर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनमोहन सिंह ने इस मामले की जांच करने के बाद हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक को अपना विस्तृत उत्तर भेजा, - उनके पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अनुसार यह कहते हुए कि इस इंस्पेक्टर के रेडियो सिद्धांत के कमजोर ज्ञान के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां इस दावे पर आधारित थीं कि उन्होंने भारत सरकार के समन्वयन पुलिस वायरलेस निदेशालय द्वारा आयोजित ग्रेड I परीक्षा में योग्यता

प्राप्त नहीं की थी और उच्च न्यायालय के C.W.P. संख्या 2025 के 1968 में निर्णय के मद्देनजर इसे अंततः आग्रह नहीं किया जा सकता था। यह और टिप्पणी की गई कि पुलिस वायरलेस के अधीक्षक ने कभी भी याचिकाकर्ता के रेडियो सिद्धांत के ज्ञान की जांच नहीं की और ये प्रतिकूल टिप्पणियां महत्वहीन हैं और इन्हें अनदेखा किया जा सकता है। उप पुलिस महानिरीक्षक की इस सिफारिश के प्राप्त होने पर, हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक ने श्री तरलोक नाथ, पुलिस अधीक्षक (वायरलेस) को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के काम और आचरण का न्यायिक और गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहा और यह कि उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा ग्रेड । परीक्षा पास न कर पाने के आधार पर टिप्पणियों को दोहराना नहीं चाहिए था। इस बीच, याचिकाकर्ता ने उचित चैनल के माध्यम से हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री को 1 अगस्त, 1972 को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए पत्र लिखा, ताकि विभाग में की गई कुछ अनियमितताओं को उनके ध्यान में लाया जा सके, जिन्हें याचिकाकर्ता ने पहले ही अपने प्रतिनिधित्व में 8 मई, 1972 और 15 मई, 1972 को हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक को बताया था। फिर पुलिस महानिरीक्षक ने इन अनियमितताओं का विवरण देने पर जोर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी, 1973 को यह विवरण प्रदान किया। इन पत्रों की प्रतियां रिट याचिका के अनुबंध पी.6 और पी.7 के रूप में संलग्न की गई हैं। इन प्रतिनिधित्वों को पुलिस के उप महानिरीक्षक श्री पी. सी. वाधवा को जांच के लिए सौंपा गया, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक, वायरलेस, हरियाणा श्री तरलोक नाथ के कार्यालय का दौरा किया और उनकी उपस्थिति में याचिकाकर्ता पर दबाव डाला कि वह इन आरोपों को वापस ले लें। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा करने से इनकार करने पर, श्री पी. सी. वाधवा ने याचिकाकर्ता को इन आरोपों को साबित करने का मौका दिए बिना, रिपोर्ट किया कि याचिकाकर्ता इन आरोपों को साबित करने में असफल रहे थे। इस पृष्ठभूमि के साथ, यह बताया गया है कि 1 अप्रैल, 1972 से 30 सितंबर, 1972 तक की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता को 8 मार्च, 1973 को फिर से प्रतिकूल टिप्पणियां बताई गईं। उनके प्रतिनिधित्व पर, पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक, वायरलेस, हरियाणा से टिप्पणी मांगी कि वर्ष 1972-73 के लिए केवल छह महीने की रिपोर्ट क्यों लिखी गई और वार्षिक रिपोर्ट नहीं। तदनुसार, पुलिस अधीक्षक, वायरलेस, हरियाणा ने अनुबंध पी.10 के पत्र में उत्तर दिया कि यह रिपोर्ट पूरे प्रासंगिक वर्ष के लिए मानी जाए। हालांकि, वर्ष 1972-73 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए प्रतिनिधित्व को पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा द्वारा स्वीकार किया गया, - विदेश पत्र दिनांक 16 सितंबर, 1974 (अनुबंध पी. 11) पुलिस उप महानिरीक्षक एच.ए.पी. को संबोधित किया गया, लेकिन इसे कभी याचिकाकर्ता को बताया नहीं गया। यह और बताया गया है कि अपने अच्छे रिकॉर्ड के मद्देनजर याचिकाकर्ता के पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए अनुशंसा अप्रैल 1974 में की गई थी जैसा कि अनुबंध पी.12 द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन बाद में पूछताछ पर, पुलिस अधीक्षक वायरलेस, हरियाणा ने उपरोक्त स्पष्ट कारणों के लिए

अनुबंध पी.13 के पत्र में तथ्यों को गलत बताया और इसके आधार पर याचिकाकर्ता को पुलिस उप महानिरीक्षक वायरलेस के पद के लिए पदोन्नति के लिए अनदेखा किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक श्री मनमोहन सिंह, एच.पी.ए. हरियाणा ने याचिकाकर्ता के पदोन्नति के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के खाली पद के खिलाफ मामले की अनुशंसा की, लेकिन कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ जांच अभी भी लंबित है। तब पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस उप महानिरीक्षक श्री मनमोहन सिंह को निर्देश दिया कि वे जांच पूरी करें और यह इस स्थिति में था कि याचिकाकर्ता को 7 अगस्त, 1974 को एक अस्पष्ट आरोपों का सारांश दिया गया ताकि याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके बाद 3 जून, 1975 तक कुछ नहीं हुआ, जब पुलिस उप महानिरीक्षक, हिसार रेंज द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ वही आरोपों का फिर से तीसरी बार सारांश दिया गया, - अनुबंध पी. 16 के पत्र के अनुसार। याचिकाकर्ता ने विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि अधिकारियों ने उपरोक्त शिकायतों के कारण याचिकाकर्ता को पीड़ित करना जारी रखा और उसे 30 अगस्त, 1974 से कुशलता बार पर रोक दिया गया, - आदेश अनुबंध पी. 17, दिनांक 18 दिसंबर, 1974 के अनुसार। याचिकाकर्ता इस आदेश को इस आधार पर चुनौती देता है कि यह वर्ष 1971-72 की टिप्पणियों और 1 अप्रैल, 1972 से 30 सितंबर, 1972 तक की छह महीने की टिप्पणियों पर आधारित था, जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं थीं क्योंकि वे पहले ही अनुबंध P2 के आदेश द्वारा मिटा दिए गए थे। फिर याचिकाकर्ता ने कुशलता बार पर रोक के खिलाफ 17 जनवरी, 1975 को पुलिस महानिरीक्षक को प्रतिनिधित्व किया, लेकिन यह प्रतिनिधित्व पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा रोक दिया गया और दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता ने फिर 28 जुलाई, 1976 को हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक को उचित चैनल के माध्यम से संबोधित एक और प्रतिनिधित्व दायर किया जिसे पुलिस अधीक्षक, वायरलेस के कार्यालय में डायरी संख्या 71516 दिनांक 29 जुलाई, 1976 को प्राप्त किया गया, लेकिन इसे कभी पुलिस महानिरीक्षक हरियाणा को अग्रेषित नहीं किया गया और अंततः, विभाग ने याचिकाकर्ता से काफी कनिष्ठ इंस्पेक्टर श्री किशोरी लाल को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया।

2) इसके बाद याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 1402 का 1978 हरजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का मामला दायर किया, जिसे उच्च न्यायालय ने 8 मई, 1978 को खारिज कर दिया क्योंकि हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक ने लिखित बयान में कहा था कि याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड के आधार पर और नहीं इस आधार पर कि उसने ग्रेड । परीक्षा पास नहीं की थी, पदोन्नति से वंचित किया गया था। इसके बाद, श्री तरलोक नाथ, पुलिस अधीक्षक वायरलेस ने याचिकाकर्ता को बार-बार प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर अनुचित तरीके से वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। याचिकाकर्ता ने हर बार सेवानिवृत्ति तक

प्रतिनिधित्व किया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन और प्रशिक्षण) श्री इकबाल सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक वायरलेस को याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1976 और 4 सितंबर, 1978 को दिए गए आवेदनों को भेजने का निर्देश दिया, जो उस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक वायरलेस ने उपरोक्त प्रतिनिधित्व के लिए अपना पैरावार उत्तर भेजा। श्री इकबाल सिंह ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक वायरलेस को भी व्यक्तिगत सुनवाई दी और उसके बाद मई 1979 में पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा श्री मनमोहन सिंह को कुशलता बार की सफाई की सिफारिश की, जो याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और उन्होंने जून 1979 के अंत तक कोई आदेश नहीं दिया। इसके बाद। श्री पी. सी. वाधवा ने हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभाला और उन्होंने याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण होकर, 55 वर्ष की आयु में याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया। - 7 जुलाई, 1979 के आदेश द्वारा (अनुबंध पी.19)। याचिकाकर्ता को वास्तव में 13 अगस्त, 1979 से सेवानिवृत्त किया गया था। कुशलता बार को पार करने की अनुमति देने के लिए याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व भी श्री पी, सी, वाधवा द्वारा 31 जुलाई, 1979 को याचिकाकर्ता को पहले ही 7 जुलाई, 1979 का आदेश प्राप्त होने के बाद अनियमित रूप से खारिज कर दिया गया था। इसके आगे यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता को छह महीने की अनुपयोगी छुट्टी के एनकैशमेंट का लाभ नहीं दिया गया और श्री पी. सी. वाधवा द्वारा याचिकाकर्ता की पेंशन में 5 रुपये की कटौती भी की गई। पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा,—उनके 19 जनवरी, 1980 के आदेश (अनुबंध पी.21) द्वारा। इसके आगे यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए इन प्रतिकूल आदेशों के खिलाफ प्रतिनिधित्वों को संबंधित अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया।

3) इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता 18 दिसंबर, 1974 के आदेश (अनुबंध पी.17) को रद्द करने की मांग करता है जिसने 30 अगस्त, 1974 से उसे कुशलता बार को पार करने से रोक दिया था और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इसके खिलाफ उसके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने का आदेश। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है और कम से कम उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति कानूनी रूप से उचित नहीं थी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय छह महीने की अनुपयोगी छुट्टी के एनकैशमेंट की अनुमति नहीं देने और याचिकाकर्ता की पेंशन से प्रति माह 5 रुपये की कटौती लागू करने के आदेशों को भी इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिकारी उससे ऊपर वर्णित आवेदन के कारण नाराज थे जिसमें संबंधित अधिकारियों की गलत कार्यवाहियों को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था, इसलिए उपरोक्त सभी आदेश मनमाने और बदनीयती से पारित किए गए थे।

4) सूचना पर, श्री योगेंद्र पॉल, पुलिस अधीक्षक वायरलेस, हरियाणा ने सभी प्रतिवादियों की ओर से लिखित बयान दायर किया, जिसमें इस रिट याचिका की स्थायित्वता को प्रारंभिक रूप से चुनौती दी गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया पूर्व C.W.P. संख्या 1402 का 1978, जो लगभग समान आधारों पर था, को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 8 मई, 1978 को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के आरोपों को गुणात्मक रूप से खंडित किया गया था। दूसरी ओर, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण को देखते हुए, याचिकाकर्ता को कुशलता बार पर रोकने, उसे पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत न करने, उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति से पूर्व की छह महीने की छुट्टी का एनकैशमेंट रोकने और पेंशन में 5 रुपये की कटौती करने से संबंधित उपरोक्त आदेश पूरी तरह से उचित थे। यह भी कहा गया था कि C.W.P. संख्या 2025 का 1968 को उच्च न्यायालय ने तकनीकी आधारों पर स्वीकार किया था क्योंकि इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति के लिए ग्रेड । परीक्षा पास करने की योग्यता,—कार्यकारी निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता की ऐसी पदोन्नति के बाद जारी किए गए थे, उन्हें लागू नहीं माना जाता था।

5) मैंने पक्षों के वकीलों को सुना है और साथ ही रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। इस न्यायालय के सिंगल बेंच के फैसले का निरीक्षण, जो C.W.P. संख्या 2025 का 1968 में वर्तमान याचिकाकर्ता हरजीत सिंह द्वारा हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक और अन्य[1] के खिलाफ दायर किया गया था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के पुलिस वायरलेस के इंस्पेक्टर से उप-निरीक्षक के पद पर वापसी का आदेश इसलिए निरस्त किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता के इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति के बाद जारी किए गए ग्रेड । परीक्षा पास करने के लिए कार्यकारी निर्देश लागू नहीं होते थे। इसके बाद, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति को पुनः बहाल किया और उसे वायरलेस के इंस्पेक्टर के रूप में वापस लाया गया। इसलिए यह कहना कि ग्रेड । परीक्षा पास न करना याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण को प्रभावित करेगा, जबकि वह इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, यह कल्पना से परे है, लेकिन ऐसी अकादमिक योग्यता की कमी को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर आगे पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण का मूल्यांकन करते समय विचार किया जाना चाहिए था। मामला यहीं पर नहीं रुकता क्योंकि याचिकाकर्ता की पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित होने की शिकायत प्रारंभिक रूप से बार द्वारा रोकी गई है क्योंकि पूर्व C.W.P. संख्या 1402 का 1978, जो समान आधारों पर था, उच्च न्यायालय द्वारा 18 मई, 1978 को खारिज कर दिया गया था।

6) कुशलता बार पर 30 अगस्त, 1974 से याचिकाकर्ता को रोके जाने के संबंध में,—18 दिसंबर, 1974 को पारित आदेश (अनुबंध पी.17) के अनुसार, यह पता चलता है कि यह

[1] 1969 एस.एल.आर. 845.

आदेश याचिकाकर्ता की वर्ष 1970-71 और 1 अप्रैल, 1972 से 30 सितंबर, 1972 की गोपनीय टिप्पणियों पर आधारित था जिसे आपत्तिजनक आदेश अनुबंध पी.17 में निम्नलिखित प्रभाव में पुनः प्रस्तुत किया गया है:–

> "यह निरीक्षक रेडियो सिद्धांत में कमजोर है। वह कठिन कार्यकर्ता नहीं है। वह ग्रेड । रेडियो सिद्धांत पास करने के लिए विशेष रुचि नहीं लेता है जबकि उसके जूनियर्स ने इस कोर्स को पास किया है। वह अपने स्वयं के हित के लिए सरकारी फाइलों से कागजात निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं लेता है। इसके लिए उसे फटकारा गया है। यह निरीक्षक वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवांछनीय टिप्पणियाँ उठाने में संकोच नहीं करता है। उसमें टीम भावना की कमी है। उसे सतर्कता और सुधार की आवश्यकता है।"

7) जहां तक 1 अप्रैल, 1972 से 30 सितंबर, 1972 की अवधि के लिए ऊपर पुनः प्रस्तुत आपत्तिजनक टिप्पणियों का संबंध है, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर, पुलिस महानिरीक्षक ने,—विधि पत्र दिनांक 7 अगस्त, 1973 (अनुबंध पी.9) द्वारा पुलिस अधीक्षक वायरलेस, हरियाणा से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों वर्ष 1972-73 के पूरे वर्ष के लिए नहीं बल्कि 1 अप्रैल, 1972 से 30 सितंबर, 1972 की अवधि के लिए ही टिप्पणियां भेजी गईं। तब पुलिस अधीक्षक वायरलेस से वर्ष 1972-73 के वार्षिक टिप्पणियों को तुरंत मांगा गया था,—विधि पत्र दिनांक 17 सितंबर, 1973 (अनुबंध पी.10) के माध्यम से। पुलिस अधीक्षक वायरलेस ने गोपनीय रिपोर्ट में संशोधन किया जिसके अनुसार इसे 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक पढ़ा जाना चाहिए। पत्र दिनांक 16 जुलाई, 1974 (अनुबंध पी.2) का अवलोकन जो हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक एच.ए.पी. को लिखा गया था, यह दर्शाता है कि हरजीत सिंह के वर्ष 1972-73 के आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व को विचार किया गया और टिप्पणियां हटा दी गईं। यह आगे उल्लेखित है कि हरजीत सिंह को इसके अनुसार सूचित किया जाए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील का आरोप है कि कुशलता बार (अनुबंध पी.17) पर रोक लगाने का आदेश, जो पहले ही हटाए गए नॉन-एस्ट आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आधारित था,—विधि पत्र अनुबंध पी.11 द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को कुशलता बार पर रोके जाने में वजन नहीं रखना चाहिए था। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व का केवल एक हिस्सा स्वीकार किया गया था और कुछ टिप्पणियों को संशोधित किया गया था, जैसा कि 2 नवंबर, 1973 को पुलिस महानिरीक्षक हरियाणा द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर पारित आदेश (अनुबंध आर.1) से स्पष्ट है। इस विवाद की उचित समझ के लिए, आदेश अनुबंध आर.1 का पुनरुत्पादन आवश्यक है। यह निम्नलिखित है:—

मैंने निरीक्षक हरजीत सिंह के प्रतिनिधित्व को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे लगता है कि कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से उचित नहीं हो सकती हैं। इसलिए, निम्नलिखित टिप्पणियों को हटाया जा सकता है: –

(अ) "और वह तीन बार ग्रेड । तकनीशियन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका।" "ये टिप्पणियां हटाई जा रही हैं क्योंकि इसी तरह की पिछली रिपोर्ट्स पर आधारित समान सलाह पहले ही उन्हें दी जा चुकी है। इसलिए केवल निम्नलिखित टिप्पणियां बनी रहेंगी: –

"कि उसका रेडियो सिद्धांत कमजोर है"

(ब) नीचे दी गई टिप्पणियां उचित हैं और बनी रहेंगी: –

"कि वह अपने रेडियो सिद्धांत को सुधारने के लिए कोई विशेष रुचि नहीं लेता है, जबकि उसके जूनियर्स ने प्रश्न में परीक्षा पास कर ली है और वह कठिन कार्यकर्ता नहीं है।"

(स) किसी व्यक्ति की ईमानदारी पर संदेह करना सरकारी फाइल से कुछ पेपर्स की प्रतिलिपि उत्पन्न करने के लिए बहुत कठोर है। सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना सरकारी रिकॉर्ड से प्रतिलिपि उत्पन्न करना अविवेकी, अनियमित और अनधिकृत हो सकता है। इसलिए, इन टिप्पणियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाना चाहिए:

"उसने सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना कुछ कार्यालय के कागजातों की प्रतिलिपि उत्पन्न की, जो क्रिया अविवेकी, अनियमित और अनधिकृत है। इस क्रिया के लिए उसे फटकारा गया था।"

(द) "वह सीधा नहीं है" वाली टिप्पणियां बहुत कठोर हैं और इसलिए मैं उन्हें हटाने के लिए इच्छुक हूं। केवल निम्नलिखित टिप्पणियां बनी रहेंगी।

"वह वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवांछित टिप्पणियां उठाने में संकोच नहीं करता है।"

(ई) निम्नलिखित टिप्पणियां बनी रहेंगी: –

"कि उसमें टीम भावना की कमी है और उसे सुधार के लिए निगरानी की आवश्यकता है।"

उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में एक स्पष्ट दृष्टि यह बताती है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाई गईं थीं लेकिन शेष टिप्पणियों को संशोधित और पुनः आकार दिया गया था। प्रतीत होता है कि पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय की ओर से हरजीत सिंह याचिकाकर्ता को पुलिस उप महानिरीक्षक एच.ए.पी. के माध्यम से यह सूचना देने में कुछ चूक हुई थी कि आपत्तिजनक टिप्पणियां हटा दी गई थीं, हालांकि कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां याचिकाकर्ता की क्षमता के बारे में बनी रहीं। इसलिए, यह वह प्रकार का मामला नहीं है जहां संबंधित प्राधिकरणों ने अस्तित्व में न होने वाली

किसी रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता को कुशलता बार पर रोकने का आदेश आधारित किया हो। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील में कोई बल नहीं है।

8) याचिकाकर्ता के उस शिकायत के संबंध में जो उनके समयपूर्व/अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर है जब उन्होंने 55 वर्ष की आयु प्राप्त की,—दिनांक 7 जुलाई, 1979 (अनुलग्नक P.19) के आदेश के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय का निर्णय CWP सं. 2025 का 1968 में जो यह कहता है कि ग्रेड । परीक्षा पास करने की शर्त याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होगी क्योंकि उन्हें निरीक्षक के रूप में पदोन्नति पहले ही दी जा चुकी थी जब ऐसी योग्यता कार्यकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित की गई थी, याचिकाकर्ता के काम के मूल्यांकन के लिए एक खाली संरक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा, उनके रेडियो सिद्धांत के ज्ञान के संबंध में या इस संबंध में अधिक सुधार दिखाने के लिए, इस तथ्य के अलग से कि हालांकि उन्होंने ग्रेड । परीक्षा पास नहीं की है, फिर भी अनुभव के कारण इस क्षेत्र में पर्याप्त कुशलता हासिल की है जिससे उनकी आगे की पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण किया जा सके। हरियाणा सरकार के इस तरह के मामलों में प्रासंगिक निर्देश पत्र दिनांक 3 सितंबर, 1968 में निहित हैं जो मुख्य सचिव सरकार, हरियाणा द्वारा सभी विभागाध्यक्षों आदि को पंजाब सरकार के पहले के पत्र दिनांक 19/21 मई, 1964 के संदर्भ में लिखे गए थे जिसमें 55 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए विस्तृत निर्देश शामिल थे। हरियाणा राज्य द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बनाए रखा जाएगा जिन्होंने उत्कृष्ट या बहुत अच्छी या अच्छी रिपोर्टें अर्जित की हैं और जिनका औसत रिकॉर्ड है उन्हें उस आयु के बाद सेवा में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में, याचिकाकर्ता औसत रिपोर्टें अर्जित कर रहा है, यहां तक कि अगर उपर्युक्त आपत्तिजनक टिप्पणियों को वर्ष 1972-73 के लिए ध्यान में नहीं लिया जाता है। वर्ष 1978-79 की नवीनतम रिपोर्टों में याचिकाकर्ता के काम और आचरण को औसत के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें यह टिप्पणी है कि वह अपने काम में सुधार दिखा रहा है लेकिन उसे और अधिक सुधार करना चाहिए ताकि वह योग्य घोषित हो सके। विशेष टिप्पणियों के कॉलम में यह आगे दर्शाया गया है कि वह एक औसत प्रकार का निरीक्षक है जो असंतुष्ट है। ये टिप्पणियां हरियाणा के पुलिस अधीक्षक वायरलेस द्वारा दी गई थीं लेकिन पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन और प्रशिक्षण) ने "असंतुष्ट" शब्द से सहमति नहीं जताई। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपने काम और आचरण के बारे में कोई भी अच्छी रिपोर्ट अर्जित नहीं की, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 55 वर्ष की आयु में समयपूर्व/अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश (अनुलग्नक P-19) प्राधिकरणों द्वारा किसी बाहरी विचारों पर गलत तरीके से पारित किया गया था। बृज मोहन सिंह

चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अनुपात, प्रतिवादी राज्य की सहायता करता है न कि याचिकाकर्ता के मामले की, क्योंकि हाल के अतीत का सेवा रिकॉर्ड ध्यान में रखा गया है और सेवा रिकॉर्ड की दूर और पुरानी प्रविष्टियों को उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश के लिए आधार नहीं बनाया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता को आपत्तिजनक प्रविष्टियों का संचार नहीं किए जाने का कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को कुशलता बार को पार करने की अनुमति नहीं थी और उसके खिलाफ याचिका भी विफल रही थी जो बदले में यह दर्शाता है कि वह योग्य और कुशल अधिकारी नहीं था और इस प्रकार उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में थी और नियमों की भावना का उल्लंघन नहीं करती है।

9) फिर सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति से पहले छह महीने की छुट्टी के भुगतान का लाभ प्राप्त है और क्या प्राधिकरणों द्वारा याचिकाकर्ता की पेंशन में 5 रुपये की कटौती करना उचित था। इस संबंध में, इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा ओ. पी. विज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[3] के मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है। उस मामले में पंजाब सिविल सेवा नियमों के भाग । खंड । के नियम 3.26 (डी) और खंड ॥ के नियम 5.32-ए (सी) का उल्लेख करते हुए, निर्णय के पैराग्राफ 4 में इस न्यायालय के पहले के एक निर्णय अमर सिंह बनाम मुख्य सचिव, पंजाब सरकार और अन्य[4] का हवाला देते हुए इस प्रकार टिप्पणी की गई थी:-

> "मैंने पक्षों के लिए सीखे वकीलों को सुना है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस अदालत के हाल के एक निर्णय, अमर सिंह सुपरिन्टेन्डेंट (सेवानिवृत्त) प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग, चंडीगढ़ बनाम मुख्य सचिव सरकार, पंजाब और अन्य, 1986(1) एसएलआर 686 पर भरोसा किया है। वह तर्क देते हैं कि उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश अनुलग्नक P.2 याचिकाकर्ता पर कोई कलंक नहीं डालता है। आदेश दंड के रूप में नहीं पारित किए गए थे और इनमें कोई दंडात्मक परिणाम नहीं है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता अनुलग्नक P-2 के आदेश के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति पर सभी पेंशनरी और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी का हकदार है। आगे अनुलग्नक P.5 के पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि स्वैच्छिक समयपूर्व सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान के हकदार हैं। नियमों में समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए दो तरीके प्रदान किए गए हैं। दिए गए शर्तों पर नियुक्ति प्राधिकरण तीन महीने की नोटिस जारी करके या तीन महीने की सैलरी के बदले में

---

[2] ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 948.

[3] 1988 (1) एस.एल.आर. 741.

[4] 1986 (1) एस.एल.आर. 686.

सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकता है। इसी तरह, एक सरकारी कर्मचारी सरकार को नोटिस देकर या सैलरी के बदले में जमा करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए, सेवानिवृत्ति की तारीख पर अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान सहित पेंशनरी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों के बीच कोई उचित वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है जो सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करके सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए, 21 अप्रैल, 1979 को अनुलग्नक P-5 के भाग में निम्नलिखित वाक्यांश भेदभावपूर्ण है और समानता के नियम का उल्लंघन करता है, और इसलिए संविधान की अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अल्ट्रा वायरस है। 'यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो सरकार द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए हैं।"

10) इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियाँ इस मामले में पूरी तरह लागू होती हैं क्योंकि यद्यपि याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु में समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई थी, फिर भी उसे अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान का लाभ प्राप्त होगा, अधिकतम 6 महीने तक। इसलिए, इस राहत को रोकने और याचिकाकर्ता के पेंशन में Rs. 5 की कटौती करने का आदेश भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह संविधान की अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसलिए, इस याचिका को उस हद तक स्वीकार करते हुए यह आदेश रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उसके क्रेडिट पर अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान करें, अधिकतम 180 दिनों तक, साथ ही याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, इस आदेश के तीन महीने के भीतर। याचिकाकर्ता को उनके पेंशन के पूरे बकाया के साथ-साथ ऐसे बकाया पर उपरोक्त दर से ब्याज भी तीन महीने के भीतर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत भी प्राप्त होगी, जिसे Rs. 1000 पर आंका गया है।

11) याचिका ऊपर बताए गए हद तक स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा